भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4752
सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

रोजगार के आंकड़े

4752. श्री रामदास तडसः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त रोजगार की संख्या सहित देश में रोजगार के सटीक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सही और सटीक आंकड़े प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात उपलब्ध सीमा तक नीचे दिया गया हैः

(प्रतिशत में)

राज्य	पीएलएफएस	श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण	
	2017-18	2013-14	2015-16
राजस्थान	48.2	54.5	53.7
महाराष्ट्र	50.5	55.2	52.2
उत्तर प्रदेश	41.8	48.1	43.7
अखिल भारत	46.8	53.7	50.5

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) और पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश सहित इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 15 जुलाई, 2019 तक 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पंचवार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। श्रम ब्यूरो भी वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करता है, जो अंतिम बार वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित किया गया था। निरन्तर अंतरालों पर श्रम बल सांख्यिकी की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान का सृजन करने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना है।

*****

अनुबंध

रोजगार के आंकड़े के बारे में लोक सभा के दिनांक 22.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4752 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	राजस्थान	13408	12614	18856
2	महाराष्ट्र*	17799	26632	45040
3	उत्तर प्रदेश	36315	43456	41928
	अखिल भारत	407840	387182	586728

* दादर और नगर हवेली सहित। स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य	सृजित मानव दिवसों की संख्या (करोड़ में)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	राजस्थान	25.97	23.98	29.42
2	महाराष्ट्र	7.09	8.25	8.46
3	उत्तर प्रदेश	15.75	18.15	21.26
	अखिल भारत	235.64	233.74	267.90

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत रखे गए नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 16-17	वि.व. 17-18	वि.व. 18-19
		नियोजित	नियोजित	नियोजित
1	राजस्थान	3397	693	3381
2	महाराष्ट्र	3694	7390	4458
3	उत्तर प्रदेश	2052	892	4839
	अखिल भारत	147883	75787	135809

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19
		नियोजित	नियोजित	नियोजित
1	राजस्थान	0	33	2765
2	महाराष्ट्र	11768	6083	20482
3	उत्तर प्रदेश	42174	30058	348
	अखिल भारत	151901	115416	163377

स्रोत: आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय